कालीशंकर दास और एक अन्य

बनाम

धीरेंद्र नाथ पात्रा और अन्य

[मुखर्जी, विवियन बोस और गुलाम हसन जे.जे]

हिंदू कानून-विधवा की संपत्ति-प्रकृति-क्या किसी को उसके जीवनकाल के दौरान संपत्ति का अधिकार मिला है-वास्तविक प्रत्यावर्तक-चाहे वह उससे पहले के अनुमानित प्रत्यावर्तक के माध्यम से दावा करता हो।

यह हिंदू कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी को भी तब तक निहित अधिकार नहीं है जब तक कि विधवा जीवित है और अंतिम रूप से प्रत्यावर्तक किसी भी व्यक्ति के माध्यम से दावा नहीं करता है जो उससे पहले गया था। उसके द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों में एक हिंदू विधवा का हित कोई समानता या सम्यता नहीं रखता है जिसे अंग्रेजी कानून में एक न्यायसंगत संपत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जिसका बिना किसी सूचना के मूल्य के लिए एक वास्तविक खरीदार के हाथों में पालन नहीं किया जा सकता है। एक हिंदू विधवा को अपनी संपत्ति में केवल योग्य स्वामित्व प्राप्त होता है जिसे वह केवल तभी अलग कर सकती है जब उचित आवश्यकता हो और उसकी अलगाव की शक्तियों पर प्रतिबंध उसकी संपत्ति से अविभाज्य हो। कानूनी आवश्यकता के लिए वह दूसरे को अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दे सकती है। यदि कोई

कानूनी आवश्यकता नहीं है तो हस्तांतरणकर्ता को केवल विधवा की संपत्ति मिलती है जो एक अक्षम्य जीवन संपत्ति भी नहीं है क्योंकि यह न केवल उसकी मृत्यु पर बल्कि पुनर्विवाह, गोद लेने आदि जैसी अन्य आकस्मिकताओं के होने पर भी समाप्त हो सकती है। अगर एक हिंदू विधवा का हस्तांतरणकर्ता यह स्थापित करने में सफल हो जाता है कि स्थानांतरण की कानूनी आवश्यकता थी, वह पूरी तरह से संरक्षित है और यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह आवश्यकता स्वयं सीमित मालिक के कुप्रबंधन द्वारा लाई गई थी। भले ही वास्तव में कोई आवश्यकता न हो, लेकिन यह साबित हो जाता है कि आवश्यकता का प्रतिनिधित्व था और वास्तविक पूछताछ करने के बाद हस्तांतरणकर्ता ने खुद को यथासंभव संतुष्ट किया कि ऐसी आवश्यकता मौजूद थी, कानूनी आवश्यकता का वास्तविक अस्तित्व बिक्री की वैधता की पूर्व शर्त नहीं है। इसलिए यदि वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है या यदि हस्तांतरणकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि उसने प्रामाणिक पूछताछ की थी और उसके अस्तित्व के बारे में संतुष्ट था, तो हस्तांतरण अमान्य नहीं है, लेकिन हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति में केवल विधवा की संपत्ति मिलेगी जो किसी भी तरह से प्रत्यावर्तक के हित को प्रभावित नहीं करती है।

देवी प्रसाद चौधरी बनाम गोलाप भगत (आई. एल. आर. 40 कैल. 721), रंगासामी गौंडेन बनाम नचियप्पा गौंडेन (46 आई. ए. 72), बजरंगी मनोकर्णिका (35 आई. ए. आई), मसुलिपटम के कलेक्टर बनाम कावली

वेंकट (8 एम. आई. ए. 529) और हुनुमन प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मत बाबूई मुनराज कूनवेरी (6 एम. आई. ए. 393) का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार 1952 की अपील सं. 108

अलीपुर के अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय के 22 दिसंबर, 1944 के डिक्री से उत्पन्न 1945 के मूल डिक्री संख्या 121 की अपील में कलकत्ता के उच्च न्यायालय के 29 मार्च, 1950 के निर्णय और डिक्री से अपील, 1941 के टाइटल सूट संख्या 70 में।

अपीलार्थियों के लिए एन.सी. चटर्जी (सी. एन. लाइक, डी. एन. मुखर्जी और उनके साथ सुकुमार घोष)।

उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए एस. पी. सिन्हा (उनके साथ बी. बी., हल्दर और एस. सी. बनर्जी)।

21 मई 1954, न्यायालय का निर्णय मुखर्जी जे. द्वारा दिया गया था।

यह अपील, जो हमारे समक्ष आई है, संविधान के अनुच्छेद 133 (1) के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर, उस न्यायालय की एक खंड पीठ के 29 मार्च, 1950 के एक फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें अपील पर, अधीनस्थ न्यायाधीश, चौथे न्यायालय, अलीपुर के 1941 के शीर्षक वाद संख्या 70 में पारित किए गए निर्णय की पुष्टि की गई है।

हमारे समक्ष वाद में, अपीलकर्ता मूल प्रतिवादी संख्या 3 के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं। जो प्रत्यर्थियों द्वारा अपने अधिकार की स्थापना पर विवादग्रस्त संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था, एक हरिपद पात्रा की माता की मृत्यु के बाद उसके प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी के रूप में, जिसे हरिपद की मृत्यु पर एक हिंदू महिला उत्तराधिकारी के प्रतिबंधित अधिकारों में संपत्ति मिली थी, इस अपील के लिए पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों की सराहना करने के लिए कालानुक्रमिक क्रम में भौतिक तथ्यों का वर्णन करना आवश्यक होगा। सूट में संपत्ति जो कलकत्ता के उपनगर में स्थित परिसर संख्या 6 द्वारिक घोष की लेन है, माना जाता है कि बंगाल के एक हिंदू निवासी महेंद्र नारायण पात्रा की संपत्ति का हिस्सा था, जिसके पास काफी संपत्ति थी, जिसकी 17 अप्रैल, 1903 को मृत्यु हो गई, जिससे वह अपनी विधवा रश्नोनी, उसके दो शिशु बेटों, मोहिनी मोहन और हरिपद और एक पूर्व मृत बेटे श्यामा चरण के पोते राम नारायण से बच गया। श्यामा चरण अपनी पहली पत्नी से महेंद्र के पुत्र थे, जिनकी मृत्यु उनके जीवनकाल में हुई थी। 17 फरवरी, 1901 को, महेंद्र ने एक वसीयत को निष्पादित किया जिसके द्वारा उन्होंने कुछ धार्मिक और धर्मार्थ स्वभाव बनाए और उनके अधीन रहते हुए, अपनी संपत्तियों को अपने शिशु पुत्रों मोहिनी और हरिपद और उनके पोते राम नारायण के बीच विभाजित करने का निर्देश दिया। वसीयत के तहत राम नारायण को निष्पादक नियुक्त किया गया था। महेंद्र की मृत्यु के बाद, राम

नारायण ने वसीयत के प्रोबेट के लिए आवेदन किया और 6 अक्टूबर, 1904 को उनके द्वारा प्रोबेट प्राप्त किया गया। राम नारायण ने संपत्ति के प्रबंधन में प्रवेश किया। उन्होंने फिजूलखर्ची और अनैतिक आदतें विकसित कीं और जल्द ही कर्ज में डूब गए। अधिकांश संपत्तियों को एक किरोनशाशी को गिरवी रखा गया था, जिसने गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री के लिए आवेदन किए गए गिरवी पर एक डिक्री प्राप्त की थी। इसके बाद राशमोनी ने अपने शिशु पुत्रों की ओर से बंधककर्ता और बंधककर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया और एक घोषणा प्राप्त की कि बंधक डिक्री उनके पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में शिशुओं के हिस्से को बाध्य नहीं कर सकती है। यह निर्णय 31 मार्च, 1909 को दिया गया था। 13 अगस्त, 1909 को महेंद्र के दो शिशु पुत्रों ने अपनी मां और अगले मित्र राशमोनी द्वारा मोहिनी और हरिपद के साथ मिलकर अलीपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जो 1909 का शीर्षक मुकदमा संख्या 45 था, जिसमें महेंद्र द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के प्रशासन के साथ-साथ उनके द्वारा छोड़ी गई वसीयत के आधार पर विभाजन और खातों का दावा किया गया था। 14 अगस्त, 1909 को, बड़ौदा कांता सरकार, जिला न्यायाधीश, अलीपुर के न्यायालय के शेरीस्तादर को, दोनों पक्षों की सहमति से, मुकदमे का विषय बनाने वाली संपत्ति का प्राप्तकर्ता नियुक्त किया गया था। इस आदेश के तुरंत बाद प्राप्तकर्ता ने संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। प्राप्तकर्ता द्वारा प्रबंधन, जैसा कि यह प्रतीत होता है, महेंद्र के दो बेटों के

हित के लिए बिल्कुल भी उचित या फायदेमंद नहीं था। महेंद्र ने स्वयं कोई ऋण नहीं छोड़ा और जो भी ऋण अनुबंधित किए गए थे, उन्हें राम नारायण ने अपने अनैतिक और फिजूलखर्ची वाले खर्चों को पूरा करने के लिए अनुबंधित किया था।

हालाँकि, प्राप्तकर्ता ने न्यायालय से प्राप्त एकतरफा आदेशों पर बड़ी राशि उधार ली, जिसका स्पष्ट उद्देश्य राम नारायण द्वारा देय ऋणों का भुगतान करना था, जो वादी पर बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं थे। इस डर से कि मुकदमा जितना लंबा चलेगा और संपत्ति प्राप्तकर्ता के हाथों में रहेगी, यह नाबालिगों के हितों के लिए उतना ही हानिकारक होगा, नाबालिगों की ओर से रशमोनी ने राम नारायण के साथ मुकदमे से समझौता किया और 13 जून, 1910 को एक सोलेनामा दायर किया गया। समझौते की शर्तें, सार में, यह थीं कि मुकदमे में संपत्तियों को तीन पक्षों के बीच विभाजित शेयरों में रखा जाना था और प्रत्येक के पक्ष में विशिष्ट आवंटन किया गया था, हरिपद के हिस्से के लिए आवंटित संपत्तियों को समझौता याचिका के साथ संलग्न अनुसूची घ और छ में निर्दिष्ट किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि प्राप्तकर्ता को अपना अंतिम लेखा जमा करने पर छुट्टी दे दी जाएगी। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि जो संपत्ति वर्तमान मुकदमे का विषय है,वह सोलेनामा के तहत हरिपद के हिस्से को आवंटित की गई थी। जिस दिन समझौता दायर किया गया था, उसी दिन राशमोनी ने रिसीवर को छुट्टी देने के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने एक

आदेश दिया जिसमें प्राप्तकर्ता को एक महीने के भीतर या जितनी जल्दी हो सके अपना अंतिम लेखा जमा करने का निर्देश दिया गया, जब निर्वहन के लिए आवश्यक आदेश दिया जाएगा। यह आगे निर्देश दिया गया कि चूंकि मुकदमे का निपटारा समझौते पर किया गया था, इसलिए प्राप्तकर्ता को उस दिन से संपत्ति के कारण किराया और लाभ एकत्र करना बंद कर देना चाहिए। हालाँकि इस आदेश को 23 जून, 1910 को दिए गए एक बाद के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि प्राप्तकर्ता को संपत्ति के कब्जे में तब तक बने रहना चाहिए जब तक कि उसे अपने सामान्य कमीशन और भत्तों के लिए जो कुछ भी देय था उसका भुगतान नहीं किया जाता है और जब तक पक्षकार अदालत में जमा नहीं करते हैं तब तक अदालत के आदेश के तहत प्राप्तकर्ता को उधार ली गई राशि या वैकल्पिक रूप से इसके लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। इसके बाद, राशमोनी ने अपने नाबालिग बेटों की ओर से अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष लगातार दो आवेदन दायर किए, जिसमें प्राप्तकर्ता के हाथों से संपत्ति को जारी करने के लिए आवश्यक धन, संपत्ति के एक हिस्से को बंधक बनाकर जुटाने की अनुमति मांगी गई। पहला आवेदन खारिज कर दिया गया था और दूसरा मंजूर कर दिया गया था, जब यह अधीनस्थ न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया था कि रिसीवर संभावित उधारदाताओं को रोकने का प्रयास कर रहा था, जिनसे राशमोनी की ओर से संपर्क किया गया था, ताकि उन्हें कोई भी पैसा उधार दिया जा सके। 16 जनवरी, 1911

को राशमोनी के छोटे बेटे हरिपद की मृत्यु हो गई और हिंदू कानून के तहत उनकी रुचि उनकी मां को उनकी उत्तराधिकारी के रूप में सौंपी गई। 28 जनवरी, 1911 को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित आदेश दर्ज किया गया थाः

"प्राप्तकर्ता ने वर्तमान महीने के अंत तक देय राशि को दर्शाते हुए एक विवरण दाखिल किया है। यह दावा रु 20,950-2-6 पाई केवल, पक्षकार 1 फरवरी को या उससे पहले अदालत में राशि जमा कर सकते हैं और इस तरह की जमा राशि पर प्राप्तकर्ता को छुट्टी दे दी जाएगी और स्वर्गीय महेंद्र नारायण पात्रा की संपत्ति का कब्जा पक्षकारों को सौंप दिया जाएगा। उसी दिन मोहिनी ने एक बंधक (उदा. एम-1) एक सुहासिनी दासी के पक्ष में, जिसके द्वारा उन्होंने अपने हिस्से के लिए आवंटित संपत्तियों और हरिपद के हिस्से में प्रत्यावर्तक के रूप में अपने भविष्य के हित को भी अनुमानित किया, ताकि रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की जा सके। 30, 000इस ऋण पर सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना था। इस बंधक के संबंध में एक बात का उल्लेख किया जा सकता है, और वह यह है कि बंधक में शामिल संपत्तियों में दो संपत्तियां थीं, अर्थात् परिसर संख्या 15/1 और 16 चेतलाहट रोड, जो पहले ही बेची जा चुकी थीं और जिन्हें बंधक की तारीख तक गिरवी रखने वाले का कोई स्वामित्व नहीं था। 1 फरवरी, 1911 को मोबिनी ने अदालत में रु 20,950-2-6 पाई, कथित रूप से प्राप्तकर्ता को देय राशि होने के कारण और अदालत ने उस तारीख को

पारित एक आदेश द्वारा प्राप्तकर्ता के हाथों से संपत्ति को जारी करने का निर्देश दिया। संपत्ति जारी होने के बाद 15 फरवरी, 1911 को वादी की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि प्राप्तकर्ता द्वारा अनुबंधित किए गए ऋणों का भुगतान अदालत में जमा किए गए धन से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उधार संपत्ति की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि केवल प्रतिवादी राम नारायण के व्यक्तिगत लाभ के लिए और अपने लेनदारों को भुगतान करने के लिए किए गए थे। यह तर्क दिया गया था कि प्राप्तकर्ता द्वारा उठाए गए ऋणों को वादी को उचित सूचना के बाद सद्भावना से नहीं उठाया गया था, बल्कि उन आदेशों के बल पर जो उसने भौतिक तथ्यों का खुलासा किए बिना अधीनस्थ न्यायाधीश से एकतरफा प्राप्त किए थे। इस आवेदन को अदालत ने 23 फरवरी, 1911 को खारिज कर दिया था।

यह आदेश दिए जाने के बाद, वादी ने एक याचिका दायर कर अनुरोध किया कि राखल दास आध्या नामक लेनदारों में से एक को भुगतान करने के लिए आवश्यक धन के अपवाद के साथ लेनदार को देय धन के भुगतान पर अगले सोमवार तक रोक लगाई जाए क्योंकि वादी ऊपर उल्लिखित अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करना चाहते थे। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 2 मार्च को उच्च न्यायालय से निम्नलिखित आदेश प्राप्त हुए जिसमें निर्देश दिया गया कि धन को आगे के आदेशों तक अदालत में

रखा जाए। उच्च न्यायालय ने 29 मई, 1911 को वादी की याचिका पर आदेश दिया। विद्वान न्यायाधीशों ने संपत्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में न्यायालय के शेरीस्तादर की नियुक्ति की बहुत आलोचना की और बिना किसी जांच के प्राप्तकर्ता के आवेदनों पर ऋण जुटाने के लिए एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश को दोषी ठहराया और प्राप्तकर्ता को संपत्ति के लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रतिवादी राम नारायण के व्यक्तिगत लाभ के लिए धन उधार लेने के लिए भी दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने एक आयुक्त द्वारा प्राप्तकर्ता के खातों की पूर्ण और उचित जांच का निर्देश दिया और उस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के एक वकील को नियुक्त किया गया। एक लंबी जांच के बाद आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेशों के तहत न केवल वादी को प्राप्तकर्ता को कोई पैसा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था, बल्कि प्राप्तकर्ता को रुपये 6,708 की राशि का भुगतान वादी को करने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी राम नारायण की ओर से 4,084 रुपये वादी को भुगतान करना था। प्रतिवादी की ओर से रुपये 19,124 प्राप्तकर्ता को भुगतान करना था और प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत रूप से उन ऋणों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था जो उन्होंने वहन किए थे। यह आदेश 23 जुलाई, 1913 को दिया गया था।

इस बीच जब उच्च न्यायालय के आदेश के तहत खातों की जांच चल रही थी, तब रशमोनी ने अपने बेटे मोहिनी के साथ मिलकर 1 अगस्त, 1911 को एक सुरक्षा बांड (एक्स ई-1) निष्पादित किया और यह इस दस्तावेज़ के कानूनी प्रभाव पर है कि इस मामले का निर्णय व्यावहारिक रूप से निर्भर करता है। मोहिनी के बंधक बांड में बंधक सुहासिनी दासी के पक्ष में निष्पादित किए गए। इस सुरक्षा बांड के माध्यम से, रशमोनी ने हरिपद के उत्तराधिकारी के रूप में मिली सभी संपत्तियों को ऋण के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में मान लिया। बंधक के तहत मोहिनी को 30,000 पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, चेतला में स्थित दो संपत्तियों को मोहिनी के बंधक में शामिल किया गया था, हालांकि वे पहले ही बेची जा चुकी थीं।

प्रतिभूति बांड में कहा गया है कि इस तथ्य का पता चलने के बाद बन्धकग्राही बंधककर्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने वाला था और यह मुख्य रूप से इन धमकी भरी कार्यवाही को रोकने और प्रतिभूति की पर्याप्तता के बारे में बंधकधारक के दिमाग से किसी भी आशंका को दूर करने के लिए था कि इस बांड को निष्पादित किया गया था। बांड में आगे कहा गया है कि उनकी मां के हाथों में हरिपद की संपत्ति को रुपये 30, 000 में से 20, 950 रुपये की राशि मोहिनी मोहन द्वारा अदालत में जमा होने से लाभ हुआ था और यह कि मोहिनी ने ऋण की शेष राशि स्वयं रशमोनी के कुछ ऋणों को चुकाने और उन दोनों के मुकदमेबाजी और

अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च कर दी थी। इसके तुरंत बाद 8 नवंबर, 1911 को मोहिनी की मृत्यु हो गई। 13 अक्टूबर, 1917 को, सुहासिनी ने रशमोनी और मोहिनी के उत्तराधिकारियों के खिलाफ बंधक और प्रतिभूति बांड को लागू करने के लिए एक मुकदमा दायर किया।

24 सितंबर, 1918 को उस मुकदमे में समझौते पर एक प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था और 25 जुलाई, 1919 को आदेश को अंतिम रूप दिया गया था। इस आदेश को लागू किया गया और 15 सितंबर, 1919 को अन्य संपत्तियों के साथ, विवादित संपत्ति को बिक्री के लिए रखा गया और इसे अन्नदा प्रसाद घोष ने 13, 500 रुपये में खरीदा।। 14 नवंबर, 1919 को राम नारायण की पत्नी भुवनेश्वरी ने अपने शिशु बेटों के संरक्षक के रूप में सुहासिनी, रशमोनी और अन्नदा के खिलाफ 1919 का शीर्षक मुकदमा संख्या 254 दायर किया, जिसमें सुहासिनी द्वारा प्राप्त बंधक डिक्री की वैधता के साथ-साथ उसके निष्पादन में बिक्री पर हमला किया गया। मुकदमा 6 जुलाई, 1921 को समाप्त हुआ और वादी ने अपना दावा छोड़ दिया। 5 सितंबर, 1922 को अन्नदा घोष ने रु 10,000 मुकदमे में मूल प्रतिवादी संख्या 3 और वर्तमान अपीलार्थियों के पिता शरत कुमार दास से उधार लिए और ऋणदाता के पास संपत्ति संख्या 6, द्वारिक घोष लेन के स्वामित्व विलेखों को न्यायसंगत बंधक के रूप में जमा किया गया। 14 सितंबर, 1925 को अन्नदा ने बंधक शरत कुमार दास के पक्ष में एक हस्तांतरण निष्पादित करके संपत्ति को रुपये में बेच दिया। 15, 500। 8

जून, 1939 को रशमोनी की मृत्यु हो गई।

लगभग एक साल बाद 15 जुलाई, 1940 को राम नारायण के तीन बेटे, जो रशमोनी की मृत्यु के बाद हरिपद के प्रत्यावर्ती उत्तराधिकारी हैं, ने अलीपुर में अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में इस आरोप पर संपत्ति के कब्जे की वसूली का दावा करते हुए वर्तमान मुकदमा शुरू किया कि रशमोनी द्वारा निष्पादित सुरक्षा बांड को कानूनी आवश्यकता द्वारा समर्थित नहीं किया जा रहा है, बंधक के निष्पादन में बिक्री के साथ-साथ शरत कुमार दास के पक्ष में बाद में हस्तांतरण केवल रशमोनी के अधिकार, स्वामित्व और हित को पारित कर सकता है और वादी के प्रत्यावर्ती अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। कई अन्य व्यक्तियों को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था और कई ऐसे मुद्दे उठाए गए थे जिनसे हम इस अपील में संबंधित नहीं हैं।

इस अपील में एक ओर वादी और दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 3 के बीच का विवाद हमारी चिंता का विषय है और यह विवाद तीन बिंदुओं पर केंद्रित है, अर्थात्

(1) चाहे प्रतिभूति बांड (उदा.ई-1) जिसे मोहिनी के साथ रशमोनी द्वारा निष्पादित किया गया था, उसे कानूनी आवश्यकता के लिए निष्पादित किया गया था और इसलिए राशमोनी की मृत्यु के बाद हरिपद के प्रत्यावर्तकों पर बाध्यकारी था?

(2) क्या यह तथ्य कि मोहिनी, जो उस समय अनुमानित प्रत्यावर्तक था, सुरक्षा बांड को निष्पादित करने में अपनी माँ के साथ शामिल हो गया था, रश्मोनी की मृत्यु के बाद वास्तविक प्रत्यावर्तक पर बाध्यकारी बना देगा? किसी भी स्थिति में यदि अनुमानित प्रत्यावर्तक की ओर से ऐसी सहमति से कानूनी आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, तो क्या उस अनुमान का वर्तमान मामले में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया था?

(3) क्या प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकार सुरक्षित था, वह एक अजनबी-खरीदार होने के नाते जिसने उचित पूछताछ करने और कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद निष्पादन बिक्री पर खरीदार से संपत्ति खरीदी थी?

विचारण न्यायाधीश ने 22 दिसंबर, 1944 के अपने निर्णय द्वारा वादी के पक्ष में इन सभी बिंदुओं का फैसला किया और मुकदमे का फैसला सुनाया। प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर, विचारण न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की गई। प्रतिवादी संख्या 3 के उत्तराधिकारी अब इस न्यायालय में आ गए हैं और अपील के समर्थन में उपस्थित श्री चटर्जी ने उन सभी तीन बिंदुओं को दोहराया है जिन पर नीचे दिए गए न्यायालयों में उनके मुवक्किलों की ओर से आग्रह किया गया था।

पहले बिंदु पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने समवर्ती रूप से अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी जो सुहासिनी के पक्ष में रशमोनी द्वारा सुरक्षा बांड के निष्पादन को उचित

ठहराए। श्री चटर्जी इस तथ्य पर जोर देते हैं कि दोनों वादी के लिए अपने पिता की संपत्ति प्राप्तकर्ता के हाथों से वापस लेना अनिवार्य आवश्यकता थी क्योंकि प्राप्तकर्ता द्वारा अनुबंधित ऋण दिन-ब-दिन बढ़ रहे थे। यह इंगित किया गया है कि 28 जनवरी, 1911 को न्यायालय ने इस आशय का एक आकस्मिक आदेश दिया था कि संपत्तियों को केवल तभी जारी किया जा सकता है जब वादी अगले साल की 1 फरवरी को या उससे पहले 20,950 रुपये जमा करें। सबसे पहले तो मोहिनी द्वारा उधार लिए गए या अदालत में जमा किए गए धन से हरिपद की संपत्ति को कोई लाभ नहीं हुआ और न ही हो सका। जैसा कि पाया गया, उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत खातों की जांच में, हरिपद या मोहिनी की संपत्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को कुछ भी देय नहीं था। दूसरी ओर, दोनों भाई प्राप्तकर्ता से काफी बड़ी राशि प्राप्त करने के हकदार थे। ट्रायल जज ने पाया कि संपत्ति को जारी करने के लिए पैसे उधार लेने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी और वास्तव में यह मोहिनी ही थी जिसने बंधक को निष्पादित करने के लिए जल्दबाजी में काम किया, उसका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति को अपने हाथों में लेना था। यह हो सकता है कि प्राप्तकर्ता के खातों के संबंध में वास्तविक स्थिति को जानना संभव नहीं था और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति के लिए खतरा माने जाने वाले धन से बचने के लिए धन जुटाना विवेकपूर्ण समझा गया होगा।

यह 28 जनवरी, 1911 को मोहिनी के पैसे उधार लेने के लिए कुछ बहाना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उस घटना के सात महीने बाद, सुरक्षा बांड को निष्पादित करने में रशमोनी का कार्य, उसकी ओर से विवेकपूर्ण प्रबंधन का कार्य या तो कानूनी आवश्यकता या उसके मृत बेटे की संपत्ति के लाभ के विचार से निर्धारित नहीं हो सका। सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोहिनी द्वारा उधार ली गई कुल राशि रु जिसमें से 30,000 रु.में से केवल 20,950 को अदालत में जमा करने की आवश्यकता थी। प्रतिभूति बांड में यह कहा गया है कि बाकी पैसा मोहिनी ने खुद रशमोनी के कुछ ऋणों का भुगतान करने और उन दोनों के मुकदमेबाजी और घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायाधीश ने गलत ठहराया है। तथ्यों पर यह पाया गया है कि रशमोनी के पास मुकदमेबाजी के खर्च या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई ऋण लेने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा बांड के निष्पादन के समय वास्तव में मौजूद चीजों की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है। भले ही संपत्ति की रिहाई को वांछनीय माना जाता था, लेकिन यह पहले से ही मोहिनी द्वारा पूरा किया जा चुका था, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर पैसे उधार लिए थे। यह सबसे अधिक कहा जा सकता था कि रशमोनी मोहिनी को इस हद तक प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य था कि मोहिनी द्वारा धन जमा करने से हरिपद की संपत्ति को लाभ हुआ था। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि राशमोनी ने जमा के

अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए कोई धन जुटाने के लिए बांड का निष्पादन नहीं किया था और वास्तव में उस उद्देश्य के लिए धन जुटाने की कोई आवश्यकता उस समय मौजूद नहीं थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अधीनस्थ न्यायाधीश के 23 फरवरी, 1911 के आदेश के खिलाफ मोहिनी और उनकी मां की पुनरीक्षण याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश द्वारा, दोनों पक्षों की सहमति से एक लेनदार को दी गई एक छोटी राशि को छोड़कर, 1फरवरी, 1911 को अदालत में जमा की गई पूरी राशि को अदालत में रोक लिया गया था।

उच्च न्यायालय ने 29 मई, 1911 को पुनरीक्षण मामले का निपटारा किया और उसके द्वारा नियुक्त आयुक्त द्वारा प्राप्तकर्ता के खातों की जांच का निर्देश दिया। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न्यायालय ने प्राप्तकर्ता के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायाधीश के आचरण पर कठोर प्रतिबंध लगाए और स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि प्राप्तकर्ता द्वारा उधार लिए गए धन को वादी के लाभ के लिए उधार नहीं लिया गया था। निस्संदेह खातों की जांच अभी भी की जानी थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर बताए गए आदेश के बाद, रश्मोनी को निष्पादित करने की क्या आवश्यकता हो सकती है, एक प्रतिभूति बांड जिसके द्वारा उन्होंने उन सभी संपत्तियों को गिरवी रख दिया जो हरिपद को उनके हिस्से में आवंटित की गई थीं, 30,000 रुपये के पूरे ऋण के लिए एक अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में। हमारी राय में सुरक्षा बांड को निष्पादित करने का एकमात्र उद्देश्य मोहिनी की रक्षा करना था, जिसे

बंधक बांड में एक गैर-मौजूद संपत्ति को शामिल करने के लिए उसके लेनदार द्वारा कानूनी कार्यवाही की धमकी दी गई थी। रशमोनी ने निश्चित रूप से मोहिनी के कहने पर और उसके लाभ के लिए काम किया और हो सकता है कि वह अपने बेटे को वास्तविक या काल्पनिक खतरे से बचाने के लिए मातृ स्नेह की भावना से प्रेरित हुई हो। लेकिन कल्पना के किसी भी विस्तार से इसे एक हिंदू महिला उत्तराधिकारी की ओर से एक विवेकपूर्ण कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता था जो अंतिम पुरुष धारक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। हमारी राय में नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण काफी उचित है और तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष के रूप में इस न्यायालय द्वारा इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री चटर्जी द्वारा आग्रह किया गया दूसरा बिंदु इस सवाल को उठाता है कि क्या मोहिनी के प्रतिभूति बांड को निष्पादित करने में अपनी माँ के साथ शामिल होने का तथ्य लेनदेन को वास्तविक प्रत्यावर्तक पर बाध्यकारी बना देगा, क्योंकि मोहिनी लेनदेन की तारीख में हरिपद का अनुमानित प्रत्यावर्तक है। हमें नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कानून को लेकर कोई गंभीर विवाद हो सकता है। यहाँ अलगाव बंधक के माध्यम से था और इसलिए आत्मसमर्पण का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता था। मोहिनी तत्काल प्रतिवर्ती होने के नाते जो प्रतिभूति बांड के निष्पादन में शामिल हुए थे, उन्हें लेन-देन के लिए सहमति दी जानी चाहिए। इस तरह की सहमति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लेन-देन कानूनी

आवश्यकता के लिए था या कि बंधककर्ता ने उचित और प्रामाणिक जांच के बाद इसमें काम किया था और

ऐसी आवश्यकता के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट किया है (1)। लेकिन यह धारणा खंडन योग्य है और यह स्थापित करने के लिए वास्तविक प्रत्यावर्तक के लिए खुला है कि वास्तव में कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी और बंधककर्ता द्वारा कोई उचित और प्रामाणिक जांच नहीं की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालय कानून के सही दृष्टिकोण पर आगे बढ़े हैं और दोनों मामले में साक्ष्य पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तत्कालीन प्रत्यावर्तक द्वारा लेन-देन के लिए सहमति देने के कारण उत्पन्न हुई धारणा का साक्ष्य में निहित तथ्यों द्वारा खंडन किया गया था।

श्री चटर्जी ने एक अन्य दस्तावेज पर काफी भरोसा किया जो घोषणा पत्र होने का दावा करता है और जिसे राम नारायण ने 5 अक्टूबर, 1918 को निष्पादित किया था। इस समय मोहिनी की मृत्यु हो चुकी थी और राम नारायण हरिपद की संपत्ति को तुरंत वापस करने वाले थे और इस विलेख द्वारा उन्होंने अन्य बातों के साथ घोषणा की कि रशमोनी द्वारा अनुबंधित ऋण उचित और कानूनी आवश्यकता के लिए थे। यह विलेख बंगशीदारी घोष और केशव दत्त, मोहिनी और हरिपद की संपत्तियों के दो अन्य सहायकों को संबोधित करने का इरादा रखता है और नीलामी खरीदार

अन्नदा प्रसाद घोष या वर्तमान अपीलकर्ताओं के पिता को किए गए अभ्यावेदन के बराबर नहीं है। वास्तव में वे तस्वीर में नहीं आए थे. उस समय बिल्कुल भी नहीं। अधिक से अधिक इसे केवल एक अनुमानित प्रत्यावर्तक द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में माना जा सकता है और इसका मोहिनी द्वारा व्यक्त की गई सहमति से अधिक मूल्य नहीं हो सकता है, जिसे प्रतिभूति बांड के सह-निष्पादक के रूप में माना जाता है। यह वास्तविक प्रतिवर्ती को किसी भी तरह से बांध नहीं सकता है। श्री चटर्जी ने बजरंगी बनाम मोनोकर्णिका (2) के मामले में सीट्रैन टिप्पणियों के अधिकार पर एक तर्क रखने का प्रयास किया कि चूंकि वर्तमान अपीलकर्ता राम नारायण के पुत्र हैं, इसलिए उनके पिता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति उन्हें भी बाध्य करेगी। यह सच है कि मोनोकर्णिका के मामले (2) में निर्णय के अंत में एक मार्ग है जो विद्वान वकील के तर्क को कुछ स्पष्ट समर्थन देता है। निर्णय के समापन शब्द इस प्रकार हैंः

"मतादीन सिंह और बैजनाथ सिंह के माध्यम से दावा करने वाले अपीलकर्ताओं को उनके पिता की सहमति से बाध्य होना चाहिए। लेकिन इस परिच्छेद के वास्तविक महत्व पर प्रिवी काउंसिल द्वारा रंगासामी गौंडेन बनाम नचिप्पा गौंडेन (1) में अपनी बाद की घोषणा में चर्चा की गई थी और यह माना गया था कि ऊपर उल्लिखित शब्दों को इस प्रस्ताव को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए कि पिता की ओर से ऐसी सहमति उचित रूप से काम करेगी और बेटों पर बाध्यकारी होगी। यह

प्रस्ताव, उनके प्रभुओं ने देखा, सिद्धांत और अधिकार दोनों के खिलाफ था, यह हिंदू कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी को भी निहित अधिकार नहीं है जब तक कि विधवा जीवित है और अंतिम रूप से पलटने वाला किसी के माध्यम से दावा नहीं करता है जो उससे पहले गया था। जैसा कि राम नारायण के पुत्र हरिपद के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं न कि अपने पिता के, इसलिए हरिपद द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, यदि कोई हो, उन्हें किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकती थी। इसलिए अपीलार्थी का यह तर्क विफल होना चाहिए। श्री चटर्जी द्वारा उठाया गया तीसरा और अंतिम तर्क यह है कि किसी भी मामले में उनका मुवक्किल एक अजनबी है जिसने उचित पूछताछ करने और उचित कानूनी सलाह पर अच्छे विचार के लिए संपत्ति खरीदी है और इसलिए वह कानूनी आवश्यकता के अभाव के कारण स्वामित्व की किसी भी कमजोरी से प्रभावित नहीं हो सकता है। हमारी राय में इस रूप में तैयार किए गए विवाद में वास्तव में एक हिंदू विधवा की संपत्ति के विदेशी की कानूनी स्थिति की गलत धारणा शामिल है। उसके द्वारा विरासत में मिली संपत्तियों में एक हिंदू विधवा का हित कोई सादृश्य या समानता नहीं रखता है जिसे अंग्रेजी कानून में एक न्यायसंगत संपत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जिसका पालन बिना किसी सूचना के एक प्रामाणिक खरीदार के हाथों में नहीं किया जा सकता है। बहुत प्रारंभिक काल से हिंदू विधवा की संपत्ति को केवल तभी अलगाव की शक्तियों के साथ योग्य स्वामित्व के रूप में वर्णित किया गया

है जब उचित आवश्यकता हो, और अलगाव की शक्तियों पर प्रतिबंध उसकी संपत्ति से अविभाज्य हैं (3)। कानूनी आवश्यकता के लिए वह किसी अन्य को अपनी संपत्ति का पूर्ण अधिकार दे सकती है।

यदि कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, तो हस्तांतरणकर्ता को केवल विधवा की संपत्ति मिलती है जो एक अक्षम्य जीवन संपत्ति भी नहीं है क्योंकि यह न केवल उसकी मृत्यु पर बल्कि पुनर्विवाह, गोद लेने आदि जैसी अन्य आकस्मिकताओं के होने पर भी समाप्त हो सकती है। यदि एक हिंदू विधवा से कोई विदेशी यह स्थापित करने में सफल होता है कि स्थानांतरण की कानूनी आवश्यकता थी, तो वह पूरी तरह से संरक्षित है और यह मायने नहीं रखता है कि यह आवश्यकता स्वयं सीमित मालिक के कुप्रबंधन द्वारा लाई गई थी। भले ही वास्तव में कोई आवश्यकता न हो, लेकिन यह साबित हो जाता है कि आवश्यकता का प्रतिनिधित्व था और प्रामाणिक पूछताछ करने के बाद विदेशी ने खुद को यथासंभव संतुष्ट किया कि ऐसी आवश्यकता मौजूद थी, तो जैसा कि प्रिवी काउंसिल ने हुनुमन परसौद पांडे के मामले (1) में बताया कि कानूनी आवश्यकता का वास्तविक अस्तित्व बिक्री की वैधता की पूर्व शर्त नहीं है। इसलिए स्थिति यह है कि यदि वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है या यदि हस्तांतरणकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि उसने प्रामाणिक पूछताछ की थी और उसके अस्तित्व के बारे में संतुष्ट था, तो हस्तांतरण निस्संदेह अमान्य नहीं है, लेकिन हस्तांतरणकर्ता को संपत्ति में केवल विधवा की संपत्ति मिलेगी जो

किसी भी तरह से प्रत्यावर्तक के हित को प्रभावित नहीं करती है। इस मामले में अलगाव बंधक के माध्यम से था। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों का निष्कर्ष यह है कि ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी जो प्रतिभूति बांड के निष्पादन को उचित ठहराए। बंधककर्ता यह भी साबित नहीं कर सका कि कानूनी आवश्यकता का प्रतिनिधित्व था और उसने प्रामाणिक पूछताछ से खुद को संतुष्ट किया कि ऐसी आवश्यकता मौजूद थी। इस बिंदु पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष इस प्रकार हैः

"वर्तमान मामले में, इस तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है कि कानूनी आवश्यकता का ऐसा प्रतिनिधित्व था या कि प्रामाणिक जांच पर हस्तांतरणकर्ता ने खुद को संतुष्ट किया कि ऐसी आवश्यकता थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रतिभूति बांड में ही कहा गया है कि यह पहले से प्राप्त लाभों के विचार में था और सुहासिनी को मोहिनी के खिलाफ कार्यवाही करने से रोकने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, कि बांड का निष्पादन किया जा रहा था। बॉन्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है कि अलगाव संपत्ति को कोई लाभ प्राप्त करने या संपत्ति को किसी भी खतरे को रोकने या किसी अन्य कानूनी आवश्यकता के उद्देश्य से किया गया था। अपीलकर्ताओं ने जो भी पूछताछ की होगी, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब अलगाव पूरी संपत्ति पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि केवल राशमोनी की महिला की संपत्ति पर है।

हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण काफी उचित है। इस निष्कर्ष पर प्रतिभूति बांड केवल रश्मोनी की विधवा की संपत्ति पर काम कर सकता था और यह केवल वही ब्याज था जो बंधक बिक्री में खरीदार को जाता था। बाद में हस्तांतरणकर्ता यह दावा नहीं कर सकता था कि उसने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कोई अधिक अधिकार प्राप्त किया है और यह मायने नहीं रखता कि उसने खरीद के पैसे का ईमानदारी से भुगतान किया या उचित कानूनी सलाह ली। परिणाम यह है कि हमारी राय में उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और इस अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।